

भारत सरकार  
शिक्षा मंत्रालय  
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2590  
उत्तर देने की तारीख-17/03/2025

**शिक्षा के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना**

†2590. डॉ. शशि थरूर:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार की शिक्षा के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने की पहल के फलस्वरूप सम्पूर्ण देश में कितने विद्यालयों और महाविद्यालयों में डिजिटल कक्षाएं विद्यमान हैं;
- (ख) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली बच्चों के पास डिजिटल शिक्षा उपकरणों (मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप आदि) की उपलब्धता के संबंध में कोई आंकड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार की ग्रामीण विद्यालयों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन छात्रों को डिजिटल उपकरण प्रदान करने की कोई योजना है जिनके पास ऐसे उपकरण नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अंतर्गत इन डिजिटल पहलों के परिणामस्वरूप छात्रों के प्रदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण नामांकन में सुधार के प्रतिशत की निगरानी करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री जयन्त चौधरी)**

(क) से (घ): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग वर्ष 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना - समग्र शिक्षा को लागू कर रहा है। यह स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12वीं तक का एक व्यापक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में लागू किया जाता है और स्मार्ट कक्षा सहित विभिन्न घटकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आज तक, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को 1,31,548 स्मार्ट कक्षाएं स्वीकृत किए गए हैं।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। भारत सरकार तीन वर्ष की अवधि के चक्र के साथ कक्षा III, V,

VIII और X के लिए नमूना आधारित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएसएस) कार्यक्रम लागू कर रही है। एनएसएस 2021 दिनांक 12.11.2021 को आयोजित किया गया था और इसमें (क) सरकारी स्कूल (केंद्र सरकार और राज्य सरकार); (ख) सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल; और (ग) निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल शामिल थे। एनएसएस 2021, “राज्य स्तर पर डिजिटल उपकरणों तक पहुँच रखने वाले छात्रों का प्रतिशत” का डेटा **अनुलग्नक** में रखा गया है।

सरकार समग्र शिक्षा के तहत छात्रों को डिजिटल डिवाइस उपलब्ध नहीं कराती है। तथापि, सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रस्ताव के आधार पर शिक्षकों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराती है। आज तक की स्थिति के अनुसार, 15.72 लाख शिक्षकों को शिक्षण संसाधन पैकेज के रूप में डिजिटल उपकरण दिए जा चुके हैं।

एनईपी 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने और शिक्षा में डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए, पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल लागू की गई है, जो शिक्षा तक बहु-मोड पहुँच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है, जिसका लक्ष्य देश भर में लगभग स्कूल जाने वाले 25 करोड़ बच्चों को लाभान्वित करना है। इस पहल के प्रमुख घटक हैं दीक्षा - देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा, कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए 200 पीएम ई-विद्या डीटीएच टीवी चैनल, डिजिटल पुस्तकों और ई-सामग्री का प्रसार करने के लिए ई-पाठशाला पहल, ई-जादुई पिटारा एक डिजिटल ऐप है जो वास्तविक जादू पिटारा का पूरक है, दीक्षा मंच पर निर्मित वर्चुअल लैब्स पर एक वर्टिकल जहां कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विषयों के लिए विज्ञान और गणित के लिए वर्चुअल लैब उपलब्ध कराए गए हैं।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की उपरोक्त डिजिटल पहल, विशेष रूप से "आईसीटी और स्मार्ट कक्षा घटक" छात्रों को बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं और कक्षा को तकनीक-संचालित कक्षा में बदल देते हैं। छात्र मल्टीमीडिया सामग्री और इंटरैक्टिव गतिविधियों में अधिक संलग्न होते हैं, जबकि संसाधनों की व्यापक श्रेणी तक उनकी पहुँच होती है। यह छात्रों के लिए गहरी समझ, सहयोग और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देता है, जिससे उनका समग्र शैक्षिक अनुभव समृद्ध होता है।

वर्तमान में इन डिजिटल पहलों के परिणामस्वरूप छात्र प्रदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण नामांकन में सुधार के प्रतिशत को ट्रैक करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि वे स्कूल प्रशिक्षण के पूरक तंत्र के रूप में काम करते हैं। तथापि, छात्रों के अधिगम परिणाम का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है। हाल ही में, 4 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख (समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) द्वारा सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वेक्षण एनईपी 2020 के अनुसार फाउंडेशन, प्रारंभिक और मध्य चरणों के अंत में चरण-विशिष्ट दक्षताओं की उपलब्धि को समझने के लिए एक आधारभूत अध्ययन है। यह देश भर के स्कूलों के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करता है।

\*\*\*\*\*

‘शिक्षा के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना’ के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. शशि थरूर द्वारा पूछे गए दिनांक 17.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2590 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

एनएसई 2021 के आंकड़ों के अनुसार डिजिटल उपकरणों तक पहुंच रखने वाले छात्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कक्षा 3 में डिजिटल उपकरण तक पहुंच रखने वाले छात्रों का प्रतिशत	कक्षा 5 में डिजिटल उपकरण तक पहुंच रखने वाले छात्रों का प्रतिशत	कक्षा 8 में डिजिटल उपकरण तक पहुंच रखने वाले छात्रों का प्रतिशत	कक्षा 10 में डिजिटल उपकरण तक पहुंच रखने वाले छात्रों का प्रतिशत
1	जम्मू एवं कश्मीर	67	69	61	79
2	हिमाचल प्रदेश	87	90	71	90
3	पंजाब	92	94	76	96
4	चंडीगढ़	91	95	77	96
5	उत्तराखंड	77	79	69	82
6	हरियाणा	77	83	69	85
7	दिल्ली	88	91	73	94
8	राजस्थान	62	65	61	78
9	उत्तर प्रदेश	57	61	55	68
10	बिहार	52	55	53	68
11	सिक्किम	80	84	70	93
12	अरुणाचल प्रदेश	52	67	62	85
13	नागालैंड	65	74	66	87
14	मणिपुर	62	69	64	81
15	मिजोरम	74	79	69	88
16	त्रिपुरा	59	61	57	76
17	मेघालय	52	60	53	75
18	असम	52	58	55	73
19	पश्चिम बंगाल	55	65	55	73
20	झारखंड	57	59	56	71
21	ओडिशा	57	62	59	79
22	छत्तीसगढ़	61	64	60	78

23	मध्य प्रदेश	60	66	60	79
24	गुजरात	69	75	65	82
25	दमन और दीव	82	86	71	89
26	दादरा एवं नगर हवेली	77	75	72	81
27	महाराष्ट्र	74	77	66	86
28	आंध्र प्रदेश	63	66	62	76
29	कर्नाटक	66	69	64	80
30	गोवा	92	93	75	97
31	लक्षद्वीप	87	92	70	94
32	केरल	94	95	76	97
33	तमिलनाडु	64	64	64	81
34	पुदुचेरी	72	79	72	91
35	अंडमान और निकोबार द्वीप	77	83	66	89
36	तेलंगाना	67	75	64	82
37	लद्दाख	74	84	69	88